Garment Exporters Association of Rajasthan

ESTD. - 28/03/1978

GEAR ACTIVITIES & EVENTS HELD FROM OCTOBER 2021 TO SEPTEMBER 2022

PRESIDENT: MR. VIMAL SHAH
GENERAL SECRETARY: MR. ASHISH AHUJA

Zakir Husain (Vice President), Lalit Kumar Arora (Vice President), Rakshit Poddar (Joint Secretary), Arun Gupta(Treasurer), Sharad Mundra (Joint Treasurer)

E.C. MEMBERS: Akash Gupta, Amit Maheshwary, Arun Lashkery, Dinesh Gupta, G. P. Mittal, Mahesh Kr. Maheshwari, Monu Karnani, Navin Adwani, Piyush Dhadda, Purshottam Gupta, Rajat Rungta, Ram Babu, Ravi Poddar, Vikas Agarwal, Vivek Khandelwal, Rajiv Dewan (Ex-President), Aseem Kumar (Ex- GS)

OCTOBER, 2021

Meeting with Hon'ble Textile Secretary

- Hon'ble Textile Secretary Shri U.P. Singh Ji visited Jaipur on 1st Oct, 2021 and held a meeting with GEAR at Hotel Marriott for discussing various concerns of our trade.
- Several suggestions were put forth in front of the Textile Secretary. Assurance was given by him that the welfare of garment and textile industry will be on priority, it being the 2nd largest employment generating sector and one of the major contributors to India's GDP.
- GST rates on fabric which was 5% at that time was requested not to be raised further.
- An appeal by Shri Rafik Khan Ji was made for opening an Apparel Park in Jaipur.

GARMENT EXPORTERS
ASSOCIATION OF RAJASTHAN

welcome

GARME PORTERS
ASSOCIA AJASTHAN
me

Discourse with CMAI Officials

- CMAI President Shri Rajesh Masand and Mentor Shri Rahul Mehta arrived in Jaipur on special invitation by GEAR.
- A meeting took place on 1st Oct,2021 where in depth discussions were held related to their future plans, shows/fairs and various other topics.
- GEAR's association with CMAI has benefitted GEAR members in the true sense.

GEAR X SOWTEX CONNECT EVENT

- GEAR Members attended the Marketing and export growth session with Marketing Consultant and Trainer Mr. Gagan Kapoor, CEO of Go for Growth Consulting, on 4th October 2021 at Hotel Marigold ,Sitapura.

Representation on GST rates

- GEAR sent a representation to various ministries regarding revision of GST rates on fabrics and garments and their implications for the garment industry.
- The representation was also sent to PMO, FM, MOT, SEC TEX, CM Rajasthan, Shri Ramcharan Bohra Ji (MP Jaipur), Shri Subhash Chandra Baheria Ji (MP Bhilwara) and others.

NOVEMBER, 2021

GEAR X HEPC EVENT

- HEPC in association with GEAR organized a seminar on 12th November, 2021 at Hotel Marigold, Sitapura.
- Presentation on the following topics were given:

1. Role & activities of HEPC
2. RODTEP and ROSCTL

- The seminar was followed by an interactive session with the esteemed speakers.

PRODUCTS
V.D. SHARMA
PRAMIT JOSHI

MEETING WITH HON'BLE FINANCE SECRETARY

- A meeting of GEAR representatives with Shri Akhil Arora Ji, Hon'ble Finance Secretary, Government of Rajasthan was held on 19th November, 2021.
- GEAR gave a representation on the revision of GST rates, expressing strong objection to this amendment and its negative ramifications for the industry.

आगामी बजट के लिए दिए सुझाव

जीएसटी और इनकम टैक्स में राहत की मांग

जयपुर @ पत्रिका. एक फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट 2022-23 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से उद्योग और व्यापारिक संगठनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें एम्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट एनके जैन, फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, राजस्थान चैम्बर के महासचिव केएल जैन सहित प्रदेश के प्रमुख उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक में आयुक्त, जीएसटी रवि जैन, शासन सचिव टी रविकांत भी उपस्थित थे।

प्रमुख सुझाव...

- जीवन बीमा पर 18 फीसदी सर्विस टैक्स शून्य हो
- होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को 1 साल के लिए जीएसटी से छूट मिले
- एमएसएमई को इनकम टैक्स में छूट मिले
- वन नेशन वन पावर टैरिफ लागू हो
- ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट पर जीएसटी 5 फीसदी किया जाए
- पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए

MEETING WITH CMAI

- A meeting was held with CMAI on 23rd November, 2021 in Mumbai in connection with the issues arising from the proposed amendment to increase GST rates on fabrics and garments.
- GEAR along with 27 Associations from different parts of country attended the meeting and was against the increase in GST rates.
- GEAR strongly opposed the amendment and protested against the same.

DECEMBER, 2021

SURAT VISIT

- Team Liva/Grasim Industries invited GEAR EC to visit their TRADC facility & Fibre Plant near Surat on 18th Dec, 2021.

It was an informative and a fruitful tour for the members.

GEAR X SOWTEX CONNECT

- GEAR in association with Sowtex Connect organized an event on Quality Management on 24th December, 2021 .
- The Session was conducted by Mr. Manjit Singh Saini, Senior Quality Consultant, Paramount Instruments
- The topic was Quality Improvement and Sustainability Norms for Apparel Exports.

JANUARY, 2022

Request to Govt. for Revision of RoSCTL Scheme

- GEAR requested the Government to review the RoSCTL scheme, the Scheme being one of the most important to garment exporters.

आरओएससीटीएल योजना की समीक्षा के लिए गारमेंट निर्यातकों ने लिखा पत्र

जयपुर | गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट योजना की समीक्षा की मांग की है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय को पत्र भी लिखा गया है। गारमेंट निर्यातकों कहना है कि योजना के तहत निर्यात किए उत्पाद में निहित कर और लेवी के मूल्य के लिए एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाती है। लेकिन आरओएससीटीएल स्क्रिप्स आपूर्ति और मांग के बीच बढ़ते अंतर से निर्यातकों का लाभ कम हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल शाह और महासचिव आशीष आहूजा ने बताया कि आरओएससीटीएल लागू करने के एक वर्ष बाद कोविड महामारी शुरू हो गई। ऐसे में निर्यातकों के लिए स्थिर नीति की जरूरत है। दरअसल, कपड़ा उद्योग में खरीदार लंबी अवधि के ऑर्डर देते हैं। वहीं निर्यातकों को गतिविधियां पहले से शुरू करनी पड़ती है। इसके मद्देनजर गारमेंट निर्यात के संबंध में स्थिर नीति की दरकरार है। वर्तमान में आयात पर आईजीएसटी के भुगतान के लिए आरओएससीटीएल स्क्रिप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर निर्यातकों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

गारमेंट एक्सपोर्टर्स का आरओएससीटीएल योजना के पुनरीक्षण का आग्रह

जयपुर,(एजेंसी)। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने आरओएससीटीएल योजना का पुनरीक्षण करने की केन्द्र से मांग की है। इन कारोबारियों का कहना है कि आरओएससीटीएल स्क्रिप्स आपूर्ति और मांग के बीच बढ़ते बेमेल के साथ, आरओएससीटीएल पर प्रीमियम काफी हद तक 80 फीसदी से कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को आरओएससीटीएल लाभ में अनपेक्षित कमी आई है। इस प्रकार की प्रतिक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रदेश के परिधान निर्यातकों ने आरओएससीटीएल योजना का बेहतर उपयोग करने के तरीकों पर गत 07 दिसम्बर को एक पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय सहित अन्य अधिकारियो को लिखा था.इस बारे में गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष विमल शाह ने बताया साल 2019 में, कपड़ा मंत्रालय ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के नाम से एक नई योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना के तहत, निर्यातकों को निर्यात किए गए उत्पाद में निहित करों और लेवी के मूल्य के लिए एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाती है। आरओएससीटीएल के शुभारंभ के ठीक एक वर्ष पश्चात कोविड-19 महामारी प्रारंभ हो गई और यह महसूस किया गया कि निर्यातकों के लिए कुछ स्थिर नीति व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता है। कपड़ा उद्योग में, खरीदार लम्बी अवधि के ऑर्डर देते हैं और निर्यातकों को अपनी गतिविधियों को पहले से ही चाक-चौबंद करना पड़ता है, यह महत्वपूर्ण है कि इन उत्पादों के निर्यात के संबंध में नीति व्यवस्था स्थिर हो।वर्तमान में, आयात पर आईजीएसटी के भुगतान के लिए आरओएससीटीएल स्क्रिप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में इसकी अनुमति केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए है। यह प्रस्तावित है कि आईजीएसटी के भुगतान के लिए भी आरओएससीटीएल स्क्रिप की अनुमति दी जा सकती है। इसका सरकार के लिए कोई राजस्व निहितार्थ नहीं होगा क्योंकि आरओएससीटीएल क्रेडिट राशि उपयोग के मकसद के लिए समान रहेगी। यह विकल्प निर्यातकों को आरओएससीटीएल स्क्रिप का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। निर्यातकों को पूर्ण मूल्य आरओएससीटीएल स्क्रिप क्रेडिट प्राप्त करना चाहिए जैसा कि इसका इरादा है। उन्होंने बताया गत 12 दिसम्बर 2021 को आपकी स्वयं द्वारा की गई बैठक के दौरान इस मामले को उठाया गया था, जहां आप इस सुझाव पर विचार करने के लिए बहुत ही सहमत हुए थे और चाहते थे कि इस मुद्दे पर एक नोट तैयार किया जाए ताकि इस मामले को राजस्व विभाग, मंत्रालय के साथ उठाया जा सके।गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी आशीष आहूजा ने बताया कि पीक सीजन चल रहा है और वर्किंग कैपिटल की बढ़ती आवश्यकता के साथ, आरओएससीटीएल स्क्रिप के उपयोग के दायरे में प्रस्तावित विस्तार निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत होगी क्योंकि रिफण्ड मूल्य में सुधार होगा, वह भी बिना किसी प्रक्रियात्मक जटिलताओं या सरकारी खजाने की अतिरिक्त लागत के होगा।

- स्क्रिप्स आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल से परिधान निर्यातकों का योजना से लाभ कम हुआ
- अधिक उत्पाद या कर जोड़ने का सुझाव
- आयात पर आईजीएसटी के भुगतान के लिए इन स्क्रिपों के उपयोग की अनुमति का आग्रह

गारमेंट एक्सपोर्टर्स का आरओएससीटीएल योजना के पुनरीक्षण का आग्रह

स्क्रिप्स आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल से परिधान निर्यातकों का योजना से लाभ कम हुआ

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

जयपुर। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने आरओएससीटीएल योजना का पुनरीक्षण करने की केन्द्र से मांग की है। इन कारोबारियों का कहना है कि आरओएससीटीएल स्क्रिप्स आपूर्ति और मांग के बीच बढ़ते बेमेल के साथ, आरओएससीटीएल पर प्रीमियम काफी हद तक 80 फीसदी से कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को आरओएससीटीएल लाभ में अनपेक्षित कमी आई है। इस प्रकार की प्रतिक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रदेश के परिधान निर्यातकों ने आरओएससीटीएल योजना का बेहतर उपयोग करने के तरीकों पर गत 07 दिसम्बर को एक पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय सहित अन्य अधिकारियो को लिखा था। इस बारे में गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष विमल शाह ने बताया साल 2019 में, कपड़ा मंत्रालय ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के नाम से एक नई योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना के तहत, निर्यातकों को निर्यात किए गए उत्पाद में निहित करों और लेवी के मूल्य के लिए एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाती है। आरओएससीटीएल के शुभारंभ के ठीक एक वर्ष पश्चात कोविड-19 महामारी प्रारंभ हो गई और यह महसूस किया गया कि निर्यातकों के लिए कुछ स्थिर नीति व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता है।

- GEAR strongly raised its voice against the policies of the government regarding export of yarn.

जयपुर। शनिवार । 22 जनवरी, 2022

बिज़नेस रेमेडीज

प्रादेशिक । मेट्रो सिटी विशेष

धागा निर्यात के बारे में सरकार की नीतियों में गंभीर बदलाव जरूरी

धागों के 70 फीसदी दाम बढ़ने से कपड़ा उद्योग पर संकट

जयपुर/का.सं.। कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले धागे के दामों में 70 फीसदी तक बढ़ोतरी होने से टेक्सटाइल उद्योग पर असर पड़ रहा है। हालांकि कोरोना काल के हालात सुधरने से मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन यहां के उत्पाद की लागत वैश्विक बाजार में मिलने वाली कीमतों के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा ब्याज पुनर्भरण पर मिलने वाली 5 प्रतिशत सब्सिडी को भी सरकार ने विगत करीब 01 अक्टूबर, 2021 से बन्द कर रखा है। जब तक कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत सरकार की नीति में कुछ गंभीर बदलाव नहीं होते हैं, तब तक सूत्र वर्तित कपड़ा उत्पादों का भविष्य काला ही नजर आ रहा है।

इस बारे में गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल शाह ने बताया कि यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश सहित अन्य कई देशों में भारत की अपेक्षा कम कीमत पर तैयार माल मिलने से कई देशों के व्यापारियों द्वारा वहां पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। धागों व कच्चे माल की कीमत बढ़ने से राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योगों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में, बांग्लादेश चीन के बाद बुनियां का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड परिधान निर्यातक है, जबकि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ भारत बड़े पैमाने पर कपड़ा निर्यात के अवसर का लाभ क्यों नहीं उठा

विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन

सका। इसका मुख्य कारण भारत में श्रम लागत का अधिक होना और सरकार की नीतियों में बदलाव का नहीं होना।

कपड़े व्यापार से जुड़े उद्योगपतियों का कहना है कि कच्चे माल के दाम 50 फीसदी बढ़ने से काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि तैयार माल महंगा होने के कारण दूसरे देशों में एक्सपोर्ट पर काफी असर पड़ा है। तैयार माल के दाम महंगे होने के कारण दूसरे देशों से ऑर्डर में भी कमी आई है।

हर सप्ताह धागों के दाम बढ़ने से ऑर्डर पूरे करने में नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश सहित अन्य देशों में धागों की कीमत कम होने के कारण विदेशी व्यापारियों द्वारा वहां पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। कपड़ा उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और धागों एवं कच्चे माल के दाम निर्धारित करने होंगे, ताकि उत्पादन लागत ज्यादा न आए।

इस बारे में एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी आशीष आहूजा ने बताया कि चौंकाने वाली बात है कि आज से 14 साल पहले यानी 2007 में बांग्लादेश की प्रतिव्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में आधी थी। एक दशक से भी कम समय में, हमारे पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी हमारी तुलना में अधिक है। इसलिए यहां की स्पीनिंग मिल्स का विस्तार पश्चात पर हैं और वे अधिक यार्न का निर्माण कर कपड़े का निर्यात करेंगी तो इसका घरेलू बाजार में काफी बुरा असर पड़ना अवश्यम्भावी है। साथ ही वे कॉटन का इम्पोर्ट करेंगी इसलिए भारत को रॉ मैटेरियल (कॉटन) के निर्यात पर अंकुश लगाने की नीति बनानी चाहिए।

कच्चा माल महंगा होने से कपड़ा व गारमेंट निर्यातक मुश्किल में

विदेशों से मिलने वाले निर्यात ऑर्डर घटे

जयपुर । यार्न की कीमतों में 70 फीसदी बढ़ोतरी से प्रदेश के गारमेंट निर्यातकों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल, कपड़ा निर्माण में बतौर कच्चा माल उपयोग होने वाले यार्न महंगा होने से गारमेंट निर्यातकों की लागत बढ़ गई है। इससे उनके उत्पाद महंगे होने से विदेशों से मिलने वाले निर्यात ऑर्डर बांग्लादेश जैसे देशों के निर्यातकों को मिल रहे हैं। वहीं, पुनर्भरण पर मिलने वाली 5 फीसदी सब्सिडी को केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 से बन्द कर रखा है। इसका भी निर्यातकों पर असर पड़ा है।

गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल शाह का कहना है कि बांग्लादेश सहित अन्य देशों में भारत की अपेक्षा कम कीमत पर तैयार माल मिलने से निर्यात ऑर्डर पर असर पड़ा है। राजस्थान के कपड़ा व गारमेंट उद्योगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

कच्चे माल की कीमत वृद्धि के साथ श्रम लागत अधिक होने और सरकार की नीतियों में खामी से बेहतर बुनियादी ढांचे के बावजूद भारत के गारमेंट निर्यातक पिछड़ रहे हैं। ऐसे में कपड़ा उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने के साथ कच्चे माल के दाम निर्धारित करने होंगे। एसोसिएशन के सचिव आशीष आहूजा का कहना है कि रॉ मेटेरियल (कॉटन) के निर्यात पर अंकुश भी जरूरी है।

कपड़ा उद्योग पर संकट: धागा निर्यात नीतियों में बदलाव जरूरी

जयपुर @ पत्रिका. कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले धागे के दामों में 70 फीसदी तक बढ़ोतरी होने से टेक्सटाइल उद्योग पर असर पड़ रहा है। हालांकि कोरोना काल के हालात सुधरने से मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन यहां के उत्पाद की लागत वैश्विक बाजार में मिलने वाली कीमतों के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा ब्याज पुनर्भरण पर मिलने वाली 5 प्रतिशत सबसिडी को भी सरकार ने अक्टूबर-2021 से बंद कर रखा है। जब तक कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत सरकार की नीति में कुछ गंभीर बदलाव नहीं होते, तब तक मूल्य वर्धित कपड़ा उत्पादों का भविष्य काला ही नजर आ रहा है। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल शाह ने बताया कि बांग्लादेश सहित अन्य कई देशों में भारत की अपेक्षा कम कीमत पर तैयार माल मिलने से कई देशों के व्यापारियों द्वारा वहां पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। धागों व कच्चे माल की कीमत बढ़ने से राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योगों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

जयपुर, शनिवार,
22 जनवरी, 2022
5

धागा निर्यात के बारे में सरकार की नीतियों में गंभीर बदलाव जरूरी

धागों के 70 फीसदी दाम बढ़ने से कपड़ा उद्योग पर संकट

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

जयपुर। कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले धागे के दामों में 70 फीसदी तक बढ़ोतरी होने से टेक्सटाइल उद्योग पर असर पड़ रहा है। हालांकि कोरोना काल के हालात सुधरने से मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन यहां के उत्पाद की लागत वैश्विक बाजार में मिलने वाली कीमतों के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा ब्याज पुनर्भरण पर मिलने वाली 5 प्रतिशत सबसिडी को भी सरकार ने विगत करीब 01 अक्टूबर, 2021से बन्द कर रखा है। जब तक कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत सरकार की नीति में कुछ गंभीर बदलाव नहीं होते हैं, तब तक मूल्य वर्धित कपड़ा उत्पादों का भविष्य काला ही नजर आ रहा है। इस बारे में गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल शाह ने बताया कि यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो क्योंकि बांग्लादेश सहित अन्य कई देशों में भारत की अपेक्षा कम कीमत पर तैयार माल मिलने से कई देशों के व्यापारियों द्वारा वहां पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। धागों व कच्चे माल की कीमत बढ़ने से राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योगों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में, बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड परिधान निर्यातक है, जबकि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ भारत बड़े पैमाने पर कपड़ा निर्यात के अवसर का लाभ क्यों नहीं उठा सका? इसका मुख्य कारण भारत में श्रम लागत का अधिक होना और सरकार की नीतियों में बदलाव का नहीं होना।

Meeting for pre-budget discussion

- Suggestions pitched forward by GEAR members for pre budget discussion with State's Tax Advisory Committee were successfully represented by Shri Dinesh Gupta Ji (Sekawati Impex) on 28th January 2022 and the committee took cognizance of queries and concerns of GEAR members.

FEBRUARY, 2022

- President Sh. Vimal Shah Ji, Gen. Secretary Sh. Ashish Ahuja Ji along with Hon'ble Textile Secretary Shri U.P. Singh Ji greeted and congratulated Shri Narendra Goenka Ji over his nomination and appointment as the new chairman of Apparel Export Promotion Council (AEPC)

MEETING WITH RIICO

- A meeting was held between RIICO MD Smt Archana Singh Ji & GEAR representatives comprising of Shri Vimal Shah Ji, Shri Ashish Ahuja Ji & Shri Rajiv Dewan Ji to discuss granting of approval to build 10 Storeyed Facility/Building for Garment Units.

गारमेंट इकाइयों को दस मंजिला तक भवन की मंजूरी मिले: गियर

जयपुर | प्रदेश के गारमेंट निर्यातकों ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में गारमेंट इकाइयों की फैक्ट्री इमारत 10 मंजिल तक बनाने की इजाजत मांगी है। निर्यातकों का कहना है कि गारमेंट इकाइयां श्रम प्रधान होने से ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (गियर) के अध्यक्ष विमल शाह ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। इसमें राज्य बजट में गारमेंट और कपड़ा इंडस्ट्री को निर्यात के लिए फ्रेट सब्सिडी की मांग की है। उन्होंने कहा कि गारमेंट और कपड़ा उद्योग से करीब पांच लाख लोगों को रोजगार मिल हुआ है। इनमें 30% से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं। अभी प्रदेश से 5,000 करोड़ रुपए के गारमेंट का निर्यात किया जा रहा है। इतना ही घरेलू कारोबार है। सरकार की थोड़ी सी मदद से गारमेंट का घरेलू कारोबार 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। गियर के सचिव आशीष आहुजा का कहना है कि प्रदेश में रिसाइक्लिंग पार्क, टेक्सटाइल सेंटरों के जरिए गारमेंट और कपड़ा इकाइयों को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। स्किल डवलपमेंट सेंटरों की भी जरूरत है। सर्टिफिकेशन लागत कम करने के लिए भी मदद की दरकार है।

विमल शाह

आशीष आहुजा

MARCH, 2022

INDIA TEX TREND FAIR, TOKYO, JAPAN

- The India Tex Trend Fair (ITTF)was held from 29th to 31st March, 2022 in Tokyo, Japan
- Shri Pawan Lashkery and Shri Vimal Shah graced the inauguration of the Show/Fair

GEAR X TEAM LIVA

- Team LIVA invited GEAR members to explore Fabric Innovations developed by their partners.
- The event was inaugurated by Sh. Vimal Shah Ji.

- GEAR would like to express its gratitude to Shri Rafiq Khan Ji for representing the industry in the legislative assembly and giving a voice to the issue of increasing yarn prices and its adverse impact on the industry.

- Hon’ble Shri Rafiq Khan Ji also highlighted the other issues being faced by the garment industry.

April, 2022

CMAI FAB SHOW, APRIL 2022

- GEAR was invited to The CMAI FAB Show that was held from 11th to 13th April, 2022 at Jio World Convention Centre, Mumbai.
- A delegation from GEAR attended the same.

MEETING WITH HON'BLE MINISTER OF STATE, TEXTILE

- Shri Vimal Shah Ji and Shri Ravi Poddar Ji met Smt. Darshana Jardosh Ji, Hon'ble Minister of State Textiles and raised the issue of increasing cotton prices and expressed concern regarding its adverse effects on Textile and Garment Industry.
- Smt. Darshana Jardosh ji assured that appropriate measures will be undertaken by the Government regarding this issue keeping the welfare of the industry in mind.

MEETING WITH HON’BLE TEXTILE COMMISSIONER

- Shri Vimal Shah and Shri Ravi Poddar met Smt. Roop Rashi Ji, Hon'ble Textile Commissioner and had a discussion about TUFF related issues.

MAY, 2022

MEETING WITH HON'BLE JOINT SECRETARY, MOT AND MD, RIICO

- GEAR delegation had a very progressive and a constructive meeting with Shri Rajeev Saxena Ji, Hon'ble Joint Secretary, Ministry of Textiles and Smt. Archana Singh Ji, RIICO MD on 6th May 2022
- A Mega Textile Park has been proposed to be built in Jodhpur which will benefit the Textile and Garment Sector of the State of Rajasthan.

- Shri Vimal Shah quoted in TOI dated 11th May 2022 regarding the high yarn and fabric prices in India.

Windfall from falling rupee is short-term, say state exporters

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The continuous depreciation of rupee has raised the earnings of the exporters, but it has also increased the cost of imports. While exporters are reaping a windfall gain, the decline in the value of rupee has made overseas education expensive.

But many exporters said that the gains are temporary, and the depreciation is not for the country because the prices of most raw materials used to produce final products have also gone up.

Dileep Baid, vice-chairman of Exports Promotion Council of Handicrafts, said that exporters who don't book forward positions will gain in the short term, but depreciation is not beneficial for the any industry.

"We import more than 80% of the oil that we consume. If oil gets costlier, the prices of every other raw material will go up. India is dependent on imports for many things. So, the depreciation of rupee will lead to price rise which in turn erode our purchasing power," said Baid who is also a leader exporter of handicrafts.

Garment export industry has a significant footprint in Rajasthan. In the past two years, the industry has been battling with high yarn prices.

Vimal Shah, president of Garment Exporters Association of Rajasthan, said, "High yarn and fabric prices have hit our margins in the past two years. The depreciation of Rupee has come as a breather for many. While it is not significant, the margins will improve a bit."

More than margins, Shah said, the industry will be able to offer competitive rates to attract buyers.

"We are losing clients to other countries because the industry could not offset the high raw material prices. The gains from the depreciation will allow us to offer competitive rates and win buyers," added Shah.

However, the depreciation is burning a hole in the pockets of many parents whose children are studying overseas. An overseas education consultant said that some parents are approaching us to find ways for them reduce the burden of currency fluctuation.

"Like big companies, the parents cannot hedge against the currency fluctuation. Because of depreciation, they have to spend more for depositing fees of their children in foreign universities. Foreign education will be costlier by at least 7-10% if the Indian rupee stays in the current levels for some months," he said.

GEAR X LIVA STUDIO

- GEAR Members were invited to explore the Spring Summer’23 collection at Liva Studio, Jaipur.

Meeting on 21st May, 2022

- A meeting was called by Secretary, Department of Finance, Government of Rajasthan, held at the Secretariat
- General Secretary Shri Ashish Ahuja ji represented GEAR , where he put forth the expectations and aspirations of GEAR for increasing the height of factories to 21mtrs from previous permissible height of 15mtrs, thereby giving an extra floor for machinery and production area which in turn will increase employment and garment production capacity.
- Subsidy for Solar power plant to be installed in factories was also emphasised and benefits for garment manufacturers in terms of non stop production, energy independence and ecological benefits were highlighted.

Meeting for inviting suggestions
regarding
RAJASTHAN INVESTMENT PRO
under the Chairmanship of Princ
Budget Announcements regardin
• Investment Friendly
• Capital Subsidy in lieu of reimbur
• Production Linked Incentives for
• Tenure Based Incentives for selecte
• Prompt and Auto disbursal of due

GARMENT TECHNOLOGY EXPO, NEW DELHI 2022 (27-30 MAY 2022)

- GEAR Members visited GTE, 2022 held in New Delhi where they got hands on experience on latest technology and advancements in the field of Garment Manufacturing.
- General Secretary Shri Ashish Ahuja & Vice President Shri Lalit Arora communicated GEAR's forthcoming technological expansion plans.

GTE
GARMENT TECHNOLOGY EXPO
Inspiring Growth
Since 2001
TRIED · TESTED · TRUSTED
GARMENT TECHNOLOGY EXPO
Best Today, Still Better Tomorrow
GTE '22
GARMENT TECHNOLOGY EXPO
INTERNATIONAL
27-30 MAY 2022
NSIC EXHIBITION COMPLEX, OKHLA, NEW DELHI

Everything for Maki
GTE NEW
GARMENT TECH
GTE '22
GARMENT TECHNOLOGY EXPO
INTERNATIONAL
27-30 MAY 2022

JUNE, 2022

SOURCEWIZ IN ASSOCIATION WITH GEAR

- Sourcewiz Exporter's Summit was held on 3rd June, 2022 at Hotel Marriott in collaboration with GEAR.
- Sourcewiz team briefed GEAR members about how their software will benefit exporters by helping them trade faster
- The event was a huge success and Sourcewiz also offered exclusive pricing to GEAR Members.

सोर्सविज़ ने राजस्थान में शुरू की सेवाएं : गियर के साथ मिलकर एक्सपोर्टर्स के बिज़नेस को देंगे रफ्तार
गियर की साझेदारी में निर्यातकों को कारोबार बढ़ाने में देगी मदद सोर्सविज
सोर्सविज और गियर मिलकर राजस्थान में निर्यातकों के बिजनेस को देंगे रफ्तार
प्रादेशिक
4
गियर के साथ मिलकर एक्सपोर्टर्स के बिज़नेस को देंगे रफ्तार
We are happy to work with Sourcewiz in our endeavour to transform the Garment Industry in Rajasthan. This collaboration addresses the strong emerging demand of exporters, they will get all industry-specific tools that are critical for the growth of their businesses.
- Vimal Shah , GEAR president
Sourcewiz

MoU BETWEEN GEAR & WWEPC

- As a special invitee, President Mr. Vimal Shah ji was invited to a meeting with Wool and Woollens Export Promotion Council (WWEPC).
- Discussion was held regarding the MoU to be signed between GEAR & WWEPC.

67th IIGF

- The 67th India International Garment Fair was held at IEML, Greater Noida from 20th - 22nd June, 2022.
- Due to GEAR'S concerted efforts, Subsidy was Granted from Department of MSME for 67th IIGF.
- Many GEAR members participated in the Fair and it was a success.

JULY, 2022

FAIRS

- GEAR Members participated in CMAI's 75th National Garment Fair held in Mumbai from 19th - 22nd July, 2022
- GEAR Members participated in The India Tex Trend Fair (ITTF)was held from 20th -22nd July, 2022 in Tokyo, Japan

FASHION REFRESH MEET: 27th – 30th July, 2022 at Liva Studio, Jaipur

- Liva Studio, Jaipur in association with GEAR organized a “Fashion Refresh Meet” where GEAR Members were invited to explore their latest collection.
- One of the LAPF partners, Nandan Denims, Ahmedabad was invited to participate in this meet and showcased their new innovative denim fabric collection.

SEMINAR

- GEAR Members were invited to attend the Seminar on “Current Scenario & Opportunities in International Trade” organized by Federation of Indian Export Organisations (FIEO) in association with Finrex Treasury Advisors LLP on 29th July, 2022 at Hotel Holiday Inn.

AUGUST, 2022

PRESS CONFERENCE

- GEAR & GEMA jointly held a Press Conference on 22nd August, 2022 to highlight difficulties being faced by Garment Exporters regarding RoSCTL Scheme.

वस्त्र निर्यात की छूट योजना से उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

जयपुर. राजस्थान वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। यहां करीब 2500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार हो रहा है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लेकिन परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने कहा, कपड़ा

उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। अपने मौजूदा स्वरूप में, स्किप पर डिस्काउंट से आयातकों को लाभ हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित फायदा उठा रहे हैं।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

राजस्थान में, रेडीमेड गारमेंट्स की निर्यात वृद्धि 2018-19 में सबसे ज्यादा 2,078 करोड़ रुपए रही थी और 2021-22 में यह बढ़कर 2,561 करोड़ हो गई, छूट योजना में असंतुलन के कारण श्रम प्रधान उद्योग कर रहा है घाटे का सामना

न्यूज ज्योति

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (RoSCTL) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा

स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (GEAR) ने कहा, कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, लखनऊ ने कहा RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब इन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 16 अरब डॉलर के कुल परिधान निर्यात में करीब 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होती है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बनती है। व्यापक स्तर पर, इस पर 20 से 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है, इससे परिधान क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मार्जिन पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ता है।

इस योजना का उद्देश्य भारत के कपड़ा क्षेत्र को अन्य कम लागत वाले देशों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम (कम श्रम और विनिर्माण लागत के कारण) के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना था। मांग सरकार की मंशा के अनुरूप रही है, जो हमेशा निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करने की थी, लेकिन स्क्रिप के डिस्काउंट के कारण, इस पूरी योजना का उद्देश्य और लक्ष्य विफल हो गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में, स्क्रिप पर डिस्काउंट से आयातकों को लाभ हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित फायदा उठा रहे हैं।

यह दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने के बजाय इस पूरी योजना के उद्देश्य और लक्ष्यों पर ही पानी फेर दे रहा है। अगर सरकार तत्काल RoSCTL की संरचना में संशोधन नहीं करती है, तो चिंता है कि लागत अक्षमताओं के कारण उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकता है। सरकार से उचित मदद न मिलने के कारण एक बार फिर परिधान मांग को अन्य कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित कर देगी।

निर्यात छूट योजना से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा प्रभावित

ब्यूरो,नवज्योति/जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ का है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीनें प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 50 -60 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी

(आरओएसटीसीएल) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं।

अपर्याप्त नकद हस्तांतरण : विमल शाह अध्यक्ष गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफराजस्थान (गियर) ने कहा कि कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को अपर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है।

केन्द्र सरकार जल्द विचार करे: विजय जिंदल सदस्य एक्सपोर्ट प्रमोशन एईपीसी और अध्यक्ष जीईएमए ने कहा आरओएसटीसीएल योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है।

'वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही है प्रभावित'

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदन करता है।

भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (RoSCTL) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं।

RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू

किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं।

विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (GEAR) ने कहा कि कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है।

विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, GEMA ने कहा RoSCTL योजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी छूट के साथ खरीदे जाते थे, लेकिन अब छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। स्क्रिप पर इतने ज्यादा डिस्काउंट से आयातकों को तो फायदा हो रहा है, जो निर्यातकों की कीमत पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

गारमेंट एक्सपोर्टर ने की तर्कसंगत छूट योजना की मांग

जयपुर, 22 अगस्त (ब्यूरो): राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा निर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग 2,500 करोड़ रूपए का है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। वहीं भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है। वहीं इन दिनों परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (आरओएसएसीटीएएल) के कारण हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को निर्यात में गिरावट आने की आशंका सता रही है। आरओएसएसीटीएएल योजना में गत वर्ष बदलाव किए गए जिसके कारण घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन कम हो रहा है। ये बदलाव निर्यातकों के लिए थे जो आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष विमल शाह व विजय जिंदल ने बताया कि सरकार इस योजना में बदलाव कर लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं।

वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा हो रही प्रभावित

जयपुर। राजस्थान वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा विनिर्माता है और राज्य का वस्त्र निर्माण उद्योग कुल 2,500 करोड़ रुपए का है। भारत में जयपुर एक प्रमुख परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख मशीने प्रतिदिन 20 लाख पीस बना रही हैं, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए दैनिक है। मौजूदा समय में यह उद्योग अकेले जयपुर में 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है जिसमें से 16 अरब डॉलर का निर्यात परिधान और वस्त्र से जुड़ा है। बड़ी मात्रा में निर्यात के अलावा ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है और 2029 तक इस उद्योग के 209 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

हालांकि, परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी (ऋासष्ट्ञह) के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15 प्रतिशत नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। RoSCTL को भारत के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव दुनिया के लिए %मेक इन इंडिया% की सरकार की घोषित नीति को बढ़ावा देने की इस पूरी योजना के उद्देश्य और मंशा पर ही पानी फेर रहे हैं। विमल शाह, अध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (तक्षक्र) ने कहा, 5कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरू करे, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनदेन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है। इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है, जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों से आयातकों को पर्याप्त नकद हस्तांतरण हो रहा है। विजय जिंदल, सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एईपीसी और अध्यक्ष, तक्षक्र ने कहा 5ऋासष्ट्ञहयोजना निर्यातकों द्वारा इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए करों, लेवी आदि के लिए छूट प्रदान करती है। इस छूट को अब उन स्क्रिप्स में बदल दिया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है। यानी निर्यातक अपनी स्क्रिप्स को आयातकों को बेच सकते हैं और आयातक, बदले में आयात शुल्क के नकद भुगतान के विकल्प के तौर पर इन खरीदे गए स्क्रिप के साथ अपने आयात शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

SEPTEMBER, 2022

THE CMAI FAB SHOW

- CMAI invited GEAR Members/Delegation for their CMAI FAB SHOW held from 19th to 21st September, 2022.
- 20 GEAR Members attended the show.

GEAR X LIVA STUDIO

- Liva Studio in association with GEAR held a AW23-24 Trend presentation cum collection launch on 22nd & 23rd September, 2022 at Liva studio, Jaipur

GEAR X CMAI

- GEAR promoted a show/fair conducted by CMAI.
- Due to the efforts of the President and General Secretary, many GEAR members were able to get the stall allotments to participate in the show even though the show was fully sold out.

THANK YOU

GEAR

Garment Exporters Association of Rajasthan

2021-22